गुजरात के लिए रेल परियोजनाएं

2568. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, गुजरात में कौन-कौन सी नई रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी,

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) :

(क) और (ख) 8 वीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वित वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

परियोजना का नाम	**अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)**	1995-96 **के बजट में उपलब्ध कराई गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1. कषडवंज-मोडाला नई बड़ी लाइन (59.71 कि0मी0)	45.00	2.00
2. गोधरा-इंदौर दाहोद, सरदारपुर, धार के रास्ते तथा देवास और मकसी (कुल 316 कि.मी.) (गुजरात राज्य में लगभग (110 कि.मी.) के बीच नई बड़ी लाइन	279.14	1.00
3. वीरमगाम से मेहसाणा आमान परिवर्तन (175 कि.मी.)	155.66	40.00
4. फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद आमान परिवर्तन (कुल 572 कि.मी.) गुजरात में 172 कि.मी.	456.57	132.43
5. राजकोट-वराबल आमान परिवर्तन (185 कि0 मी0)	100.00	1.00
6. गांधीधाम-भुज आमान परिवर्तन (58 कि0 मी0)*	26.14	2.00
7. बांकानेर-मलिया मियाणा आमान परिवर्तन (90 कि0 मी0)	51.00	35.00

* योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने पर

(ग) पर्याप्त धनराशि और सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है,

Violation of MOU by Hindustan Latex Limited

2569. SHRI V AY ALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any direction as per the Memorandum of Understanding to give purchase preference to the condoms provided by Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram;

(b) if so, whether Government have purchased condom from any other companies violating the directions of MOU; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R ANTULAY): (a) As per MOU 95-96, signed between the Government of India and Hindustan Latex Limited (HLL), Thiruvananthapuram, HLL will be given purchase preference vis-a-vis Private firms in the placement of Government orders in accordance with the overall Government Policy and Instructions in this regard.